

द बगि पक्चर: बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने का रोडमैप

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2021-2022 में बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने विकास वित्त संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की है, जिससे बड़े पैमाने पर संपत्तिका मूद्रीकरण संभव हो सकेगा।

- बुनियादी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने से न केवल महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

प्रमुख बटु

- **बजट आवंटन में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में बुनियादी अवसंरचना के लिये बजट आवंटन में 34.5% की वृद्धि की गई है।
- **सभी क्षेत्रों पर समान फोकस:** सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, शहरी बुनियादी अवसंरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, नौ-परविहन व वमानन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित सभी भौतिक अवसंरचनाओं पर समान बल दिया गया है। राजमार्गों के निर्माण के लिये 1.08 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है।
- **संस्थागत स्थापना:** सरकार ने विकासात्मक वित्तीय संस्थान की स्थापना एवं पूंजीकरण के लिये 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
- **नगिरानी एवं पारदर्शिता:** अवसंरचना विकास में हुई प्रगति को ट्रैक करने हेतु डैशबोर्ड के साथ एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी, इससे नविशक भी संबंधित कार्यों पर ट्रैक रख सकेंगे।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

- बजट 2021-22 में संभावित ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। परसंपत्त विमुद्रीकरण सार्वजनिक परसंपत्तियों में किये गए नविश जनिसे अब तक उचित अथवा संभावित रटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, को अनलॉक करने की प्रक्रिया होती है।

ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ

- ब्राउनफील्ड नविश तब होता है जब कोई कंपनी अथवा सरकारी संस्था एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिये मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदता है अथवा पट्टे (lease) पर देता है। यह **प्रत्यक्ष वदेशी नविश** (FDI) में उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है।
- इसका विकल्प एक ग्रीनफील्ड नविश होता है, जिसमें एक नए संयंत्र का निर्माण किया जाता है।

बुनियादी अवसंरचना विकास के लिये फोकस क्षेत्र

- **अवरोधों को समाप्त करना:** जो सड़कें एवं राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उनके अतिरिक्त उन अवरोधों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये जो राजमार्ग एवं शहरों को जोड़ते हैं।
- **कम लागत वाले आवास:** बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ ज्यादातर टयिर-1 टयिर-2 शहरों तक ही सीमित हैं, महामारी के पश्चात् प्रवासी मजदूर शहरों में लौटेंगे, इसलिये सरकार को कम लागत वाले आवासों पर काम करना होगा ताकि भविष्य में कोई मजदूर को अस्थायी आवास की समस्या न हो।
- शहरों को झुग्गियों से मुक्त करना तथा कम लागत वाले आवास भारत के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिनमें ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।
- **नदी पुनरुद्धार:** भारत को नदी पुनरुद्धार अवसंरचना को बढ़ावा देना होगा क्योंकि लगभग प्रत्येक शहर में एक ऐसी नदी है जिसमें अपशिष्ट जल मलित है।
 - यद्यपि प्रमुख नदियों के लिये प्रमुख कार्य योजनाएँ, जैसे- स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मशिन हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं, कई नाले एवं सहायक नदियाँ मुख्य नदी के प्रदूषण में योगदान दे रही हैं।
 - इसके अतिरिक्त इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों का सहयोग लेने की भी आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP):** सरकार इन बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में तब तक केवल अपने संसाधनों से पूर्ण नविश नहीं कर सकती

- है, जब तक कि सरकार नज्जी क्षेत्र को शामिल नहीं करती है। सरकार नज्जी क्षेत्र के सहयोग से इन परसिंपत्तियों का मुद्रीकरण कर सकती है।
- अवसंरचना परियोजनाओं को पूरण करने में होने वाली देरी को कम करने के लिये सरकारें शुरू में परियोजनाओं का नरिमाण कर सकती हैं और फरि संचालन एवं रखरखाव के लिये परियोजनाओं को नज्जी क्षेत्र को सौंप सकती हैं।

संबंधति मुददे

- **स्थायी वतित का अभाव:** हालाँकि बुनयिदी अवसंरचना के लिये बजट में का एक बड़ी राशिका आवंटन कयिा जाता है लेकिन यह तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसे बाज़ार से पूरक संसाधनों जैसे- एफडीआई के साथ संवर्धति नहीं कयिा जाता है।
- **भूमिसंबंधति मुददे:** भूमिकिसी भी बुनयिदी अवसंरचना परियोजना के लिये बुनयिदी आवश्यकता है। भारत में भूमिअधगिरहण वविदास्पद है, अतः यह प्रक्रयिा बहुत तीव्र नहीं होती है।
- **अप्रभावी वविाद समाधान तंत्र:** बहुत सारी अवसंरचना परियोजनाएँ, क्रयिान्वयन एजेंसयिों जनिहें परियोजनाएँ सुपुरद की जाती हैं एवं प्राधकिरणों के मध्य मुकदमेबाज़ी में फँस जाती हैं।
 - वविाद समाधान तंत्र बहुत तीव्र एवं प्रभावी नहीं हैं, इसलिये मौजूदा नविशकों को सफल होना मुश्कलि लगता है और नए नविशक भाग लेने में ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते हैं।

आगे की राह

- **मानव संसाधन:** बुनयिदी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं नगिरानी के लिये गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन के नविश की आवश्यकता होगी।
- **प्रत्यक्ष वदिशी नविश:** उन क्षेत्रों में जहाँ भारत अनुसंधान एवं वकिस में अभी भी वैश्वकि स्तर पर नहीं है, FDI की अनुमतिएँ FDI में वृद्धकि जानी चाहयि।
 - भारत में अधिक FDI लाने के लिये कानूनी ढाँचे को सुगम बनाना होगा एवं इसके लिये एक बेहतर अनुबंध प्रबंधन प्रणाली तथा एक वविाद समाधान तंत्र की आवश्यकता है।
- **नज्जी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकार स्वयं प्रयासों से नज्जी क्षेत्र की उद्यमति क्षमताओं को सामने नहीं ला सकती है, यदि भारत को बुनयिदी ढाँचा प्रदान करने के मामले में वैश्वकि स्तर पर पकड़ बनानी है तो इसकी बहुत आवश्यकता है।

नषिकर्ष

- PPP मॉडल के साथ बुनयिदी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने का एक रोडमैप बनाए जाने की आवश्यकता है एवं इससे सरकार की वत्तीय क्षमता पर बोझ कम होगा।
 - यद्यपि नज्जी क्षेत्र एक लाभ आधारति क्षेत्र है लेकिन इसे उपयुक्त तरीके से वनियिमति कयिा जाए तो यह सरकार, नज्जी क्षेत्र के साथ-साथ राष्टर के लिये भी लाभदायक होगा।
 - इसके अतरिकित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है जो न केवल सार्वजनकि नविश से होने वाले रटिरन में वृद्धकिरेगा बल्कि संतुलति क्षेत्रीय वकिस को भी बढ़ावा देगा।
- यदि भारत का लक्ष्य वशि्व स्तरीय बुनयिदी अवसंरचना की स्थिति प्राप्त करना है, तो कई चीज़ें हैं जनि पर धयान देने और प्रोत्साहन दयि जाने की आवश्यकता है जैसे कि अनुसंधान एवं वकिस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये उद्योग एवं शकिषा साझेदारी को प्रोत्साहन दयि जाना।